



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2018/वैशाख 14, 1940

No. 164]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2018/VAISAKHA 14, 1940

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)**

**जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना**

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

(परिवंचना रोधी जाँच-[एसी] 02/2018)

**विषय:** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की कथित परिवंचना से संबंधित परिवंचना रोधी जांच की शुरुआत।

**सं. 7/14/2018-डीजीएडी.**—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

2. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है), ने एक पाटनरोधी समीक्षा जाँच में 23 मई, 2017 की अपनी अधिसूचना सं. 14/31/2016-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए जिसमें संबद्ध वस्तु पर अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की गई जिसे 13 जुलाई, 2017 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं 35/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 19 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं 14/31/2016-डीजीएडी द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओफ्लोक्सेसिन एसिड या ओ-एसिड के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई और तदनुसार दिनांक 12 मार्च, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 6/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।

3. यतः, पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसार, मै. आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) जो भारत में ओ-एसिड के एकमात्र उत्पादक हैं, ने प्राधिकारी के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जो दिनांक 13 जुलाई, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 35/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क के अधीन है और बाद में दिनांक 12 मार्च, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 6/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधीन है, की अब भारत में परिवर्चना की जा रही है। चीन जन. गण. के निर्यातक भारत में ओफलोक्सिन ईस्टर का निर्यात कर रहे हैं जिसे बाद में किसी खास मूल्यवर्धन के बिना आसानी से ओ-एसिड में बदल दिया जाता है। ओफलोक्सिन ईस्टर का उत्पादन ओ-एसिड की विनिर्माण प्रक्रिया में अनंतिम स्तर है। अनंतिम और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के कारण, चीन से उत्पादकों ने ओफलोक्सिन ईस्टर, जो अनंतिम मध्यवर्ती उत्पाद है, का उत्पादन और निर्यात करना और ओ-एसिड पर लागू पाटनरोधी शुल्क का प्रवंचन करके भारत में उसका पाटन करना लाभकारी पाया है।

### **विचाराधीन उत्पाद**

4. परिवर्चना की वस्तु बनाने वाला उत्पाद ओफलोक्सिन ईस्टर है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अधीन उपशीर्ष 29349900 के अधीन भी वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जॉच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

### **मौजूदा उपाय**

5. वर्तमान में लागू पाटनरोधी उपाय, जिन्हें कथित रूप से प्रवंचित किया जा रहा है, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों पर दिनांक 13 जुलाई, 2017 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं 35/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया अनंतिम पाटनरोधी शुल्क और बाद में दिनांक 12 मार्च, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 6/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क है।

### **जॉच शुरूआत के आधार**

6. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों पर लगाये गए पाटनरोधी शुल्क का प्रवंचन 13 जुलाई, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 35/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद शुरू हुआ और अब वह तेज हो गया है। यह परिवर्चना "उत्पाद परिवर्चना" की श्रेणी में अधीन आती है। याचिकाकर्ता दावा करता है कि चीन जन. गण. के निर्यातक भारत में ओफलोक्सिन ईस्टर का निर्यात कर रहे हैं जिसे बाद में किसी खास मूल्यवर्धन के बिना आसानी से ओ-एसिड में बदल दिया जाता है। ओफलोक्सिन ईस्टर का उत्पादन ओ-एसिड की विनिर्माण प्रक्रिया में अनंतिम स्तर है। अनंतिम और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के कारण, चीन से उत्पादकों ने ओफलोक्सिन ईस्टर, जो अनंतिम मध्यवर्ती उत्पाद है, का उत्पादन और निर्यात करना और ओ-एसिड पर लागू पाटनरोधी शुल्क का प्रवंचन करके भारत में उसका पाटन करना लाभकारी पाया है। ओफलोक्सिन ईस्टर को ओ-एसिड में बदलने की प्रक्रिया अम्लीय जल में हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया है। ओफलोक्सिन ईस्टर को ओ-एसिड में बदलने की लागत और भारत में ओफलोक्सिन ईस्टर को ओ-एसिड में मूल्यवर्धन का स्तर पाटनरोधी नियमावली के नियम 25(ख) के अधीन यथा विहित 35 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है। ओ-एसिड के प्रयोक्ता/आयातक अब ओफलोक्सिन ईस्टर का आयात कर रहे हैं और मामूली मूल्यवर्धन के साथ उसे ओ-एसिड में बदल रहे हैं। इससे ओ-एसिड पर शुल्क निरर्थक हो गया है। इसके अलावा जुलाई, 2017 से पहले ओफलोक्सिन ईस्टर के आयात शून्य थे। तथापि, अनंतिम पाटनरोधी शुल्क के तत्काल बाद ओफलोक्सिन ईस्टर के आयात भारी मात्रा में होने शुरू हो गये। इसके अलावा, ओ-एसिड के आयात व्यवहारिक रूप से बंद हो गए अगस्त 2017 से ओ-एसिड के मात्र एक टन का आयात हुआ है। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद आयातों की प्रवृत्ति में स्पष्ट परिवर्तन हुआ है। एडीडी लागू होने से ओफलोक्सिन ईस्टर के भारी आयात हुए हैं और जुलाई, 2017 से ओ-एसिड के आयात बंद हो गए हैं। यह भी देखा गया है कि ओफलोक्सिन ईस्टर की आयात कीमत ओ-एसिड की आयात कीमत से कम है। याचिकाकर्ता ने यह आरोप भी लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को उसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम पर मध्यवर्ती रूप में संबद्ध देश से प्रवंचित किया जा रहा है, जिससे लागूपाटनरोधी शुल्क निष्क्रिय हो गया है। इसलिए घरेलू उद्योग को

वास्तविक क्षति होना जारी है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को हुई क्षतिपाटित आयातों के कारण हो रही है जिसका उपचार परिवर्चना के कारण नहीं हुआ है।

### **प्रक्रिया**

7. **संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां** से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की परिवर्चना रोधी जाँच की आवश्यकता को सही ठहराने वाले घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने पर, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(1क) के अनुसार दिनांक 13 जुलाई, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 35/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा और बाद में दिनांक 12 मार्च, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 6/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की कथित परिवर्चना की परिवर्चना रोधी जाँच के की शुरुआत के लिए पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ओफलोक्सिन ईस्टर के आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और संबद्ध देश से ओफलोक्सिन ईस्टर के आयातों के लिए दिनांक 12 मार्च, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 6/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की आवश्यकता है।

8. इस परिवर्चना जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

9. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) जुलाई 2017 – मार्च, 2018 है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल 2015 – मार्च 2016, अप्रैल 2016 – मार्च 2017 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

10. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जाएगा :-

#### **निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग**

**चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**

**नई दिल्ली- 110001**

11. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

### **समय-सीमा**

12. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

13. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

15. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पांच-पांच (5-5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

16. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

17. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

18. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

19. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

20. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2018

**(Anti-Circumvention Investigation – [AC] 02/2018)**

**Subject: -Initiation of anti- circumvention investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports of “O-Acid”, originating and exported from China PR.**

**No. 7/14/2018-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof (hereinafter referred to as the Rules or AD Rules),

2. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in an anti-dumping review investigation, vide its Notification No. 14/31/2016-DGAD dated 23<sup>rd</sup> May, 2017 issued preliminary finding recommending imposition of provisional duties on the subject goods which were imposed by the Ministry of Finance Notification No.35 /2017-Customs (ADD) dated 13<sup>th</sup> July, 2017. The Designated Authority vide Notification No. 14/31/2016-DGAD dated 19<sup>th</sup> December, 2017, notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on imports of Ofloxacin Acid or O-Acid originating in or exported from China PR and accordingly definitive anti-dumping duties were imposed vide Customs Notification No. 6/2018-Customs (ADD) dated the 12th March, 2018.
3. Whereas, in terms of the Section 9A of the Customs Tariff Act 1975, read with Rule 25 of the Anti-Dumping Rules, M/s. Aarti Drugs Limited. (hereinafter referred to as the Petitioner or the Domestic Industry), the sole producer of O-Acid in India, has filed a petition before the Authority alleging that O-Acid, which is the product subject to provisional antidumping duty vide Customs Notification No.35 /2017-Customs (ADD) dated 13<sup>th</sup> July, 2017 and later definitive anti-dumping duties, vide Customs Notification No. 6/2018-Customs (ADD) dated the 12th March, 2018 is now being circumvented into India. The exporters from China PR are exporting Ofloxacin Ester into India which is then simply being converted into O-Acid without much value addition. The production of Ofloxacin Ester is a penultimate step in the manufacturing process of O-Acid. Due to the imposition of provisional and definitive anti-dumping duty, the producers from China have found it advantageous to produce and export Ofloxacin Ester, the penultimate intermediary product and dump the same into India by evading the Anti-dumping duty imposed on O-Acid

**Product under Consideration**

4. The product forming the object of circumvention is “Ofloxacin Ester”. The subject goods are also classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under the Sub-heading 29349900. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of investigation.

**Existing Measures**

5. The measures currently in force and which are allegedly being circumvented are the provisional antidumping duty imposed by Ministry of Finance vide Customs Notification No.35 /2017-Customs (ADD) dated 13<sup>th</sup> July, 2017 and later definitive anti-dumping duties, vide Customs Notification No. 6/2018-Customs (ADD) dated the 12<sup>th</sup> March, 2018 on the imports of O-Acid, originating in or exported from China PR.

**Grounds for Initiation**

6. The Petitioner claims that the circumvention of the anti-dumping duty levied on the imports of O-Acid originating in or exported from the subject country started after the imposition of provisional anti-dumping duty vide Customs Notification No.35 /2017-Customs (ADD) dated 13<sup>th</sup> July, 2017 and the same has now intensified. This type of circumvention comes under “product circumvention”. The petitioner claims, exporters from China PR are exporting Ofloxacin Ester into India which is then simply being converted into O-Acid without much value

addition. The production of Ofloxacin Ester is a penultimate step in the manufacturing process of O-Acid. Due to the imposition of provisional and definitive anti-dumping duty, the producers from China have found it advantageous to produce and export Ofloxacin Ester, the penultimate intermediary product and dump the same into India by evading the Anti-dumping duty imposed on O-Acid. The process involved in converting Ofloxacin Ester to O-Acid is the process of hydrolysis in acidic water. The cost of converting Ofloxacin Ester to O-Acid and the value addition from the stage of Ofloxacin Ester to O-Acid in India is much below the limits of 35% as prescribed under the Rule 25(b) of the AD Rules. The users/importers of O-Acid are now importing Ofloxacin Ester and with minimal value addition converting the same to O-Acid thereby. This has left the duty on O-Acid meaningless. Also there were NIL imports of Ofloxacin Ester prior to July 2017. However, immediately after imposition of provisional antidumping duty, the imports of Ofloxacin Ester started in significant volume. Further, imports of O-Acid have practically stopped with just One MT of O-Acid being imported in Aug 2017. Thus, there is clear change in pattern of the imports post imposition of anti-dumping duty. Imposition of ADD has led to significant imports of Ofloxacin Ester and virtual stoppage of imports of O-Acid since July 2017. It is also seen that the import price of Ofloxacin Ester is lower than the import price of O-Acid. The petitioner also alleges that the product under consideration is being circumvented from the subject country in intermediary form, below its associated normal value, nullifying the dumping duty in force. Hence, the domestic industry continues to suffer material injury. Thus, injury to the domestic industry was being caused by the dumped imports, which has not been remedied because of circumvention

#### **Procedure**

7. Having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for an anti-circumvention investigation, the anti-dumping duty imposed on the imports of O-Acid originating in or exported from the subject country, the Authority has concluded that sufficient prima facie evidence exists to initiate an anti-circumvention investigation of the alleged circumvention of the anti-dumping duty imposed on the imports of O-Acid originating in or exported from the subject country vide Customs Notification No.35 /2017-Customs (ADD) dated 13<sup>th</sup> July, 2017 and later definitive anti-dumping duties, vide Customs Notification No. 6/2018-Customs (ADD) dated the 12<sup>th</sup> March, 2018 in accordance with Section 9A(1A) of the Act, read with Rule 25 of Antidumping Rules, to investigate as to whether imports of Ofloxacin Ester are at dumped prices and are causing injury to the domestic industry and the need for extending anti-dumping duty imposed on the imports of O-Acid originating in or exported from the subject country vide Customs Notification No. 6/2018-Customs (ADD) dated the 12<sup>th</sup> March, 2018 to the imports of Ofloxacin Ester from the subject country.
8. The country involved in this circumvention investigation is China PR.
9. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is July 2017 – March, 2018. The injury investigation period will, however, cover the periods April'2014- March'15, April'2015–March'2016, April'2016-March'2017 and the POI.

#### **Submission of Information**

10. The known exporter in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product shall be addressed to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

#### **The Designated Authority**

**Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties**

**Department of Commerce, Jeevan Tara Building, 4th Floor**

**5, Parliament Street**

**New Delhi -110001**

11. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out by the Authority. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limits**

12. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of communication of initiation of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.
13. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to extend the Antidumping measures on circumvented product within 40 days from the communication of initiation of this Notification.

**Submission of information on confidential basis**

14. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
  - (a) One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - (b) The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
15. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.
16. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
17. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
18. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
19. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
20. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

21. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority